

## जी.एस.टी. 2.0 ( रिफॉर्म्स का नया दौर ) केवल आशा पर निर्भर नहीं है

वित्त मंत्री आशा कर रही हैं कि इन रिफॉर्म्स के कारण रोज़मर्रा का सामान सस्ता होगा, और डिमाण्ड (मांग) बढ़ेगी

—अंजन राॅय—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। जीएसटी काउन्सिल द्वारा किए गए सुधार पूरे देश के लिए एक बड़ा बजट जैसा कदम है। यह कदम न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्यों के बजट को भी तय करने वाला अहम कारक बनेगा। माल और सेवा कर यानी जीएसटी ने सभी अप्रत्यक्ष करों (इनडायरेक्ट टैक्स) को मिलाकर एक साझा कर ढांचा बनाया था और अब यह केंद्र व राज्यों दोनों की कुल आय का बड़ा हिस्सा है।

दरअसल, जीएसटी की दरों में व्यापक बदलाव और कर की श्रेणियों को घटाने की कोशिश के पीछे क्या तर्क है? सबसे पहले, यह कर दरों की श्रेणियों को सरल बनाने और घटाने के वादे को पूरा करता है।

यह सुधार, 2017 में जीएसटी लागू करते समय शुरू हुए व्यापक कर सुधारों का ही हिस्सा है। उस समय देश में केंद्र और राज्यों की कई अलग-अलग कर व्यवस्थाएँ थीं जिन्हें मिलाकर एक समान “कर प्रणाली” यानी जी.एस.टी., बनाई गई।

- विदेश में (विशेषकर अमेरिका में) ऊंची टैरिफ के कारण भारतीय सामान के निर्यात को धक्का लगेगा। वित्त मंत्री चाहती हैं कि विदेशों में मांग घटने से व्यापार में आई कमी की भरपाई, देश में स्थानीय खपत बढ़ने से पूरी की जा सकेगी।

- टैक्स घटा कर, “इन्टर्नल डिमाण्ड” बढ़ाने का फार्मूला कई देश पहले ही अजमा चुके हैं। उदाहरण के लिये, अमेरिका में भी राष्ट्रपति रीगन की सरकार ने स्थानीय टैक्स काफी घटाये थे, तथा इससे देश में “इन्टर्नल डिमाण्ड” आंकलन से भी ज्यादा बढ़ी थी, और अमेरिका की इकॉनमी के वारे-न्यारे हो गये थे।

- पर अगर भारतीय उद्योगपतियों ने बढ़ती डिमाण्ड की पूर्ति के लिये, नया इन्वेस्टमेंट करके औद्योगिक क्षमता नहीं बढ़ाई, तो सप्लाई की पूर्ति नहीं कर पायेंगे और मंहगाई बढ़ेगी, और इकॉनमी में उल्टा चक्कर घूमने लगेगा और अगर इकॉनमी इस व्यूहरचना में फंस गई तो उससे उबरना बहुत मुश्किल होगा।

उस समय वादा किया गया था कि केवल दो टैक्स स्लैब होंगे, लेकिन व्यवहारिक कारणों से चार स्लैब लागू किए गए और लक्ष्य रखा गया कि धीरे-

प्रतिशत का “सिन टैक्स” शामिल है।

औसतन, जीएसटी केंद्र और राज्यों की कुल आय का लगभग 44 प्रतिशत है, तथा राज्यों की आय में इसका हिस्सा और भी अधिक है। इसलिए दरों में बदलाव से राज्यों की वित्तीय स्थिति केंद्र से ज्यादा प्रभावित हो सकती है। चूंकि जीएसटी की दरें काउन्सिल तय करती है और न तो केंद्र और न ही राज्य इन्हें अकेले बदल सकते हैं, इसलिए ये घोषणाएँ एक ठोस व स्थाई ढांचा देती हैं जिसके भीतर बजट बनाना अनिवार्य होगा।

नए जी.एस.टी. सुधारों की घोषणा से बजट बनाने के लिए एक आधार तय हो गया है।

जीएसटी 2.0 कहलाने वाले इस स्लैब सुधार की घोषणा पुराने बजट घोषणाओं जैसी लगी, जहाँ कर में बदलाव के असर से रोजमर्रा की चीजों की कीमतें ऊपर-नीचे होती थीं, सिगरेट महंगी, बीड़ी सस्ती, एसी महंगे, डीजल सस्ता और इसी तरह।

सवाल है कि अभी ये बदलाव क्यों? दरअसल, स्लैब घटाने और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस. आई. भर्ती : एक और अभ्यार्थी गिरफ्तार

जयपुर, 4 सितम्बर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 मामले में कार्रवाई करते हुए, एक और अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित ने परीक्षा से पहले लीक सॉल्वड पेपर पढ़ कर लिखित परीक्षा पास की थी। आरोपित ने आठ लाख रूपए में सौदा करके पेपर लेकर लिखित परीक्षा तो पास की,लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। एसओजी की

- आरोपी ने लीक सॉल्वड पेपर पढ़कर लिखित परीक्षा पास की थी, पर अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ।

टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) एसओजी वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए परीक्षा से पहले लीक सॉल्वड पेपर पढ़ कर लिखित परीक्षा पास करने वाले आरोपित रिंकू यादव (33) निवासी नगर जिला डींग भरतपुर हाल कामां जिला डींग भरतपुर को गिरफ्तार किया है। एसओजी की जांच में सामने आया कि रिंकू ने कार्तिकेय शर्मा के साथ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## कांग्रेस को “वोट चोरी” के बाद “एथनॉल मिक्सिंग” दूसरा सबसे बड़ा स्कैम नज़र आता है

कांग्रेस के मीडिया व पब्लिसिटी चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके इस नए स्कैम को साबित करने के लिये काफी आंकड़ेबाजी की

- खेड़ा के अनुसार, सात साल हुए जब भाजपा ने “एथनॉल” पेट्रोल में मिलाकर, पेट्रोल के दाम गिराने का दावा किया था, पर सात साल बाद आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ।
- भारत का प्रारंभिक वादा था, नगर पालिकाओं से निकले “वेस्ट” को एकत्रित कर उससे एथनॉल बनाया जायेगा। जिसे पेट्रोल व डीजल में मिलाकर बेचा जायेगा और पेट्रोल 55 रु. लीटर के भाव बिकेगा और इसलिये सरकार एथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने जा रही है।
- पर सात साल बाद भी म्युनिसिपल वेस्ट व लकड़ी के बुरादे से एक लीटर एथनॉल भी नहीं बना है।
- इसी प्रकार यह भी वादा किया गया था, कि एथनॉल के उपयोग से प्रदूषण कम होगा, जबकि सच तो यह है कि लीटर एथनॉल बनाने के लिये तीन हजार लीटर पानी की खपत होती है। इससे पर्यावरण का फायदा है या नुकसान।
- खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि भारत में निर्मित वाहनों में एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल से, इंजन बहुत जल्दी फुंक जाता है।

जमानती अपराध पर महिला आरोपियों को 43 दिन जेल में रखना खेदजनक

जयपुर, 4 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती अपराध होने के बावजूद, महिला आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर जेल भेजने तथा उन्हें 43 दिन तक जेल में रखने पर खेद जताया है। इसके साथ ही, अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय की ओर से पेश स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होते हुए रजिस्ट्रार को आदेश दिए हैं कि वे प्रकरण को

- हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी मशीनी अंदाज में जमानत प्रार्थना पत्र नहीं निपटायें।

जानकारी जिले के गार्जियन जज को दें। वहीं अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वे संबंधित जांच अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांग कर आगामी कार्रवाई करें। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी कहा है कि यदि उन्हें लगता है कि प्रकरण में उनके मौलिक अधिकारों की अवहेलना हुई है तो वे कानूनी प्रावधानों का सहारा ले सकती हैं। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने ये आदेश मीतू पारीक और इंदू वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, न्यायिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने माना उत्तरी राज्यों में भारी बाढ़ का प्रमुख कारण पेड़ों की अवैध कटाई है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स में बाढ़ में लकड़ी के बड़े-बड़े लट्ठे बहते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लगता है पहाड़ों पर पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है

—जाल खंबाता—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 4 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही पर गहरी चिंता जताई और पहाड़ी इलाकों में “पेड़ों की अवैध कटाई” को इसका प्राथमिक कारण माना।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के दौरान बहती लकड़ियों के वीडियो फुटेज का हवाला देते हुए कहा, “यह एक गंभीर मामला है। मीडिया रिपोर्ट्स में देखा गया है कि बाढ़ में भारी मात्रा में लकड़ी के लट्ठे बहते हुए नजर आए। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ों में पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है।

पीठ ने केंद्र सरकार को – पर्यावरण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से – और साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई और जस्टिस के. विनोदचंद्रन की बेंच ने इस बारे में सांलिंसिटर जनरल तुषार मेहता को संबोधित करते हुए कहा, ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे दिख रहे हैं इससे लगता है पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है।

- एस जी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे इस बारे में जल्दी से जल्दी पर्यावरण मंत्रालय व राज्यों के मुख्य सचिवों से बात करेंगे।

- सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय, जलशक्ति विभाग, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल हाइड्रेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजकर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। उसके बाद आगे सुनवाई होगी।

(एनडीएमए) तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर की सरकारों को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने

को कहा है। इसके बाद इस मामले की आगे सुनवाई होगी।

मुख्य न्यायाधीश ने चिंता व्यक्त (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे

कई विधायक बारिश से खराब हुई फसल भी लेकर आये

जयपुर, 4 सितम्बर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को, भारी बारिश से खराब हुई फसलों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष में बैठे कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सदन में नारेबाजी की, वैंल में आकर विरोध जताया और स्पीकर से भी तीखी बहस की। हालात इतने बिगड़े कि सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। दूसरी बार की कार्यवाही महज 33 मिनट ही चल सकी। हंगामे के बीच तीन बिल पास करवाए गए और फिर कार्यवाही सोमवार, 8 सितंबर तक के

- आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच स्थगन प्रस्तावों का जवाब दिया।

लिए स्थगित कर दी गई।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खुद ट्रैक्टर लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद कांग्रेस



नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली गुरुवार को बारिश से खराब हुई फसलों और किसानों की अनदेखी पर विरोध जताने के लिए ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा परिसर पहुंचे।

विधायक पैदल मार्च करते हुए विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई विधायक अपने हाथों में, भारी बारिश के कारण खराब हुई

फसलें भी लेकर आए थे, ताकि सरकार को जमीनी हकीकत से रूबरू कराया जा सके।

शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने अतिवृष्टि से बर्बाद हुई

फसलों का मुद्दा उठाया। विधायक अमित चाचाण और नरेन्द्र बुढ़ानिया ने कहा कि लाखों एकड़ में फसलें खराब हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने अब तक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने राजस्थान शतरंज संघ के चुनाव पर रोक लगाई

जयपुर, 4 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान शतरंज संघ के 6 सितंबर को प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में महावीर रांका, शतरंज संघ और सहकारिता विभाग को नोटिस जारी

- पूर्व में अध्यक्ष रहे महावीर रांका, शतरंज संघ व सहायता विभाग से जवाब मांगा।

कर जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश अशोक कुमार भागवत की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अखिल सिमलोट ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता राजस्थान शतरंज संघ का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

—जाल खंबाता—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को यहां एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर जमकर हमला बोला, खासकर एथनॉल नीति और जीएसटी सुधारों में देरी को लेकर।

उन्होंने जीएसटी सुधारों में आठ साल की देरी पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अब सरकार आखिरकार राहुल गांधी की लंबे समय से दी जा रही सलाह को मान रही है। राहुल गांधी ने गरीबों और व्यापारियों पर जीएसटी के प्रभाव की पुनर्समीक्षा की मांग की थी।

उन्होंने कहा, आज एथनॉल पर हम थोड़ी बात करेंगे, काफी दिनों से चर्चा चल रही है इथेनॉल पर और एथनॉल पर

दिल्ली में राहत कैंप भी पानी में डूबा

नई दिल्ली, 04 सितंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुरुवार दोपहर तक यमुना नदी का पानी खतरे के निशान से सवा दो मीटर ऊपर तक पहुंच गया।

- यमुना का पानी खतरे के निशान से सवा दो मीटर ऊपर तक पहुंच गया है।

इसकी वजह से दिल्ली और नोएडा के कई इलाके डूब गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, मयूर विहार फेज-1 का राहत शिविर भी बाढ़ के पानी में डूब गया है। रिंग रोड, अलीपुर, बुराड़ी, मयूर विहार, रिंग रोड समेत कई इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यमुना बाजार, सिविल लाइन्स समेत कई एरिया भी बाढ़ से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

यह मेरा है-यह तेरा है ऐसा संकीर्ण हृदय वाले मानते हैं। उदार चित्त वाले तो सारे संसार को एक कुटुंब समझते हैं। –हितोपदेश

क्या संविधान के अनुसार सांसद व विधायक पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं?

विधानसभा सदस्यों तथा संसद के सांसदों को वेतन व परिलब्धियां, भत्ता व पेंशन मिलती है। वेतन भत्ता व पेंशन अधिनियम, 1954 है। राजस्थान राज्य के अधिकारियों व विधायकों के वेतन भत्तों व पेंशन का अधिनियम, 1956 (Act No.6 of 1957) है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन व आवश्यक है कि इन दोनों कानूनों में प्रारम्भ में जब ये बनाये गये पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं था। इनमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। राजस्थान राज्य ने अधिनियम के तहत रूल्स बनाये हैं जो राजस्थान विधानसभा सदस्य नियम, 1977 हैं।

सेलेरीज एण्ड एलउन्सेज अधिनियम, 1954 को संशोधन किया गया और उसमें मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट शब्दावली को जोड़ा गया। इसे नई धारा 8ए से जोड़ा गया, जिसके द्वारा पेंशन देने की व्यवस्था की गई। इसका स्पष्ट अर्थ था सांसदों को वेतन भत्तों के अतिरिक्त पेंशन भी प्राप्त होगी। पेंशन की रेट में कई बार संशोधन कर वृद्धि की गई।

राजस्थान में केन्द्र के अधिनियम, 1954 की भांति विधानसभा के अधिकारियों व विधायकों को वेतन व परिलब्धियों के साथ पेंशन दिये जाने का प्रावधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पेंशन का प्रावधान राजस्थान एक्ट नं. 17/2015 व संशोधन एक्ट 26/2017 से धारा 4क के रूप में जोड़ा गया। इस प्रावधान में यह व्यवस्था है कि 1 अप्रैल, 2019 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो सदस्य 5 वर्ष तक की कालावधि के लिये निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष तक की कालवधि के रहा हो, उसे 35,000/-रूपये पेंशन दी जावेगी और उपर्युक्त पाँच वर्ष की कालावधि (टर्म) से अधिक पूरे टर्म के लिये हो तो 1600/-रूपये की अतिरिक्त पेंशन प्रतिमाह सदलत की जावेगी। सदस्य 70 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता है तो उसे 20 प्रतिशत तथा 80 वर्ष पर 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रावधान 4ख में कुटुम्बिक पेंशन की बात है। यह विधानसभा 5 वर्ष से पहले विघटित कर दी गई हो तो भी अवधि कम होने पर भी पेंशन देने के हेतु अवधि को 5 वर्ष मान लिया जावेगा। यदि सांसद व विधायक कोई संवैधानिक पद धारण करता है तो पेंशन की अदायगी सस्पेंड रहेगी।

सांसद हो अथवा विधायक 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने पर एक साधारण नागरिक की भांति हो जाता है। वह पुनः चुनाव लड़ सकता है, विधायक/सांसद बन सकता है। विधायक/सांसद रिटायर नहीं होता। पेंशन को रिटायरल बेनीफिट कहा जाता है। अधिकारी व सांसद/विधायक में अन्तर है। अधिकारी कर्मचारी है; किन्तु सांसद/विधायक जनता द्वारा Elect किये जाते हैं। साधारण रूप से जिस व्यक्ति ने सरकारी नौकरी की है अथवा जिसे सरकारी संस्थानों में जिन्हें स्टेट कहा जाता है नौकरी की है और सेवा की शर्तों के अनुसार पेंशन की व्यवस्था है उन्हें पेंशन दी जाती है। विधायक व सांसद जैसा ऊपर कहा है, रिटायर नहीं होते हैं उनका केवल टर्म समाप्त होता है और वे चुनाव में जीतने पर पुनः सदस्य बन सकते हैं। नगरपालिका, पंचायत जैसे निकायों में भी चुनाव होते हैं यह चुनाव भी निश्चित अवधि में होते हैं। वहां भी सदस्य, रिटायर नहीं होते हैं वे पुनः चुनाव लड़ सकते हैं, वहां पेंशन का कोई प्रावधान किसी भी कानून में चाहे वह पंचायत एक्ट हो अथवा यूनिसिपलिटी एक्ट (अधिनियम) नहीं है। फिर क्यों विधायकों/सांसदों को पेंशन दी जावे? यह एक विचारणीय प्रश्न है, अतः हमें संविधान को देखना होगा, पढ़ना होगा उसका अध्ययन करना होगा कि क्या पेंशन का उपरोक्त प्रावधान जो उक्त कानूनों में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है वह संवैधानिक है? साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि पेंशन किसे दी जावे, इसकी क्या व्यवस्था है? सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि हमें पेंशन शब्द की जो परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366(1) में दी है, उसकी सही व्याख्या क्या है?

हम सब देश के नागरिक हैं, यहां लोकतंत्र है, देश के लोगों ने संविधान बनाया है। देश के संचालन के लिये, नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिये उनके गरिमा मय जीवन यापन के लिये, खाद्य, चिकित्सा, देश की सुरक्षा आदि के लिये फण्ड की आवश्यकता है जिसे टैक्स लगाकर ही पूरा किया जा सकता है। अतः सरकार के फण्ड का खर्च विवेकपूर्ण होना चाहिये और संविधान द्वारा मान्य थी। सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार सन् 2021-22 में उस वर्ष 25 करोड़ 95 लाख 47 हजार 400/-रूपये का पेंशन पर खर्च था।

लेखक, पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है जो सबको झकझोर देगा कि विधायक को प्रत्येक विधानसभा के टर्म की राजस्थान में पेंशन दी जाती है। यदि कोई विधायक कई बार विधायक बनता है तो उसे उतनी ही बार की बढ़ी पेंशन मिलेगी। क्या इसका कोई औचित्य हो सकता है? यह पेंशन वर्तमान में दिनांक 1.4.2023 से 31,000/-रूपये प्रति माह है। हाँ, यदि वह दूसरे टर्म के हेतु चुनाव जीतकर सांसद बनता है तो उसे बैसिक पेंशन 31,000/-रूपये व अतिरिक्त पेंशन 5 वर्ष के टर्म लिये रु. 2,500 X 5 = रु. 43,500/- मिलेगी। सांसदों व विधायकों को वेतन के अतिरिक्त कई तरह के भत्ते दिये जाते हैं और फिर भी पेंशन। इनमें बदलेतरी होती रहती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। राजस्थान में विधयक के दूसरे टर्म की पेंशन रु. 43,000/- है और प्रत्येक टर्म में अमर्यादित रूप से बढ़ जाता है।

आइये, इस पृष्ठभूमि में हम संविधान के परिप्रेक्ष्य में पेंशन को जो सांसद व विधायक प्राप्त कर रहे हैं उसका कानूनी परीक्षण करें।

संविधान के अनुच्छेद 106 में सांसदों को वेतन व भत्ते दिये जाने का प्रावधान है, जिनका निर्धारण व प्रबन्ध समय-समय पर अधिनियम बनाकर संसद करती है। इसी प्रकार विधायकों के वेतन व भत्तों के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 195 के प्रावधान हैं। अधिनियम (एक्ट) के द्वारा वेतन व भत्ता दिया जाता है। इन दोनों प्रावधानों में पेंशन दिये जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। इसका सामान्य भाषा में अर्थ है कि संविधान सांसदों व विधायकों को पेंशन देने के बाबत अधिनियम बनाकर मनमानी कानून बनाने की अनुमति नहीं देता।

उपरोक्त कथन को बल इससे भी मिलता है जब हम संविधान की सूची 1 की एन्ट्री 73 को सांसदों के वेतन व भत्ते के बाबत कानून बनाने की अनुमति देता है। इसी प्रकार राज्य की सूची 2 की एन्ट्री 38 है जो विधायकों के भत्ते व वेतन के हेतु कानून बनाने की अनुमति देता है। सूची 1 की एन्ट्री 73 व सूची 2 की एन्ट्री 38, क्रमशः सांसदों व विधायकों को पेंशन देने की अनुमति नहीं देती है। अर्थ स्पष्ट है उपरोक्त दोनों कानूनों और उसमें हुये संशोधन अवैध, असंवैधानिक, अमान्य व शून्य है।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने राजस्थान में वेतन संशोधन अधिनियम, 2017 के द्वारा राजस्थान मंत्री अधिनियम 1956 में संशोधन के द्वारा धारा 7 बीबी व धारा 11(2) जोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सरकारी आवास व 10 व्यक्तियों का स्टाफ व ड्राइवर की सुविधा प्रदान की गई थी, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि मुख्यमंत्री ने अपने निर्धारित पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं की हो तो भी यह सुविधा उन्हें प्राप्त होगी। इस प्रावधान को राज्य के वरिष्ठ व यशस्वी पत्रकार मिलापचंद डांडिया ने एक पीआईएल रिट याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसकी फैली प्रसिद्ध एडवोकेट विमल चौधरी ने की थी। यह याचिका दिनांक 4.8.2019 के आदेश से उच्च न्यायालय से स्वीकृत हुई और उक्त प्रावधान को अवैध करार दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रावधान को निरंकुश व औचित्यहीन करार दिया। इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एएसएलपी दायर की गई, किन्तु उसे 6.1.2020 को एडमिशन स्टेज ही पर खारिज किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की डीबी का उक्त निर्णय प्रस्तुत केस पर भी लागू होता है। यहाँ भी पेन्शन का प्रावधान निरंकुश, मनमाना अमर्यादित व समाप्ता के सिद्धान्त के मूल अधिकार के विरुद्ध है। सांसदों, विधायकों, अधिकारियों को वेतन, भत्ता आदि दिये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है; किन्तु जब इनका भुगतान संविधान की मर्यादा की सीमा लांघकर निरंकुश, विवेकशून्य और विभेदकारी हो कर फ्रीबीज व लूट का रूप धारण करता है तो जनता का विरोध करना स्वाभाविक है।

सुप्रीम कोर्ट ने डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983) 1 एसएससी 305 के केस में यह विचार अभिव्यक्त किया है कि पेंशन चेरिटी नहीं है अपितु कर्मचारी द्वारा जीवन में की गई मेहनत का फल है। यह रिटायरमेंट के बाद दिया गया एक अधिकार है सांसद रिटायर नहीं होता। यह स्वीकृत सिद्धान्त है कि पेंशन सोशल सिक्युरिटी है, जबकि सांसद अपने टर्म की समाप्ति पर (जो 5 वर्ष की अवधि का होता है) रिटायर नहीं होते अपितु संसद की सीट रिक्त होती है और वह सदस्य की निरहता (Disqualification) अनुच्छेद 101 में मानी जाती है। वह स्थान चुनाव द्वारा भरा जाता है। सांसद को दुबारा चुनाव में खड़ा होने का अधिकार होता है। पेंशन अधिक आयु होने पर रिटायर होने पर दी जाती है। विधायकों रिटायर नहीं होती उनकी सीट अनुच्छेद 190 के अनुसार रिक्त होती है सदस्य को निरहता का प्रावधान अनुच्छेद 191 के अनुसार होता है। सदस्य यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह निरहिंत होगा। पेंशन पाना लाभ का पद है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो कॉमन कॉज एक पंजीकृत सोसाइटी है उसमें सांसदों की पेंशन की वैधनिकता का प्रश्न उठाया गया था; किन्तु लेखक का अपना स्वतंत्र विचार है वह निर्णय Precedent नहीं है; क्योंकि उसमें पेंशन शब्द की मूल परिभाषा जो संविधान के अनुच्छेद 366(17) में दी है, उसका उल्लेख ही नहीं है। परिभाषा के अनुसार पेंशन का आधार सेवानिवृत्त वेतन है।

अतः लेखक का मत है कि सांसद व विधायक पेंशन के अधिकारी नहीं है। सेलेरीज एण्ड एलउन्सेज व पेंशन ऑफ पार्लियामेंट अधिनियम, 1954 तथा राजस्थान विधानसभा के अधिकारियों और सदस्यों के वेतन, भत्ता व पेंशन अधिनियम (एक्ट नं. 26/2017) असंवैधानिक, अवैध व निरंकुश, औचित्य शून्य होने से प्रभाव शून्य है तथा निरस्तनीय है। जब विधायकों को दी जाने वाली पेंशन ही असंवैधानिक है फिर अतिरिक्त टर्म की पेंशन तो न केवल विवेक व औचित्य शून्य है अपितु अनैतिक भी है।

यही प्रश्न एक जनहित याचिका (पिटीशन नं. 19134/2022) मिलापचंद डांडिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के नाम से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,  
पानाचन्द जैन  
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

संपादकीय

शिक्षक ज्ञान के वाहक ही नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों के निर्माता भी हैं



वासुदेव देवनानी

भारत की सनातन सभ्यता में गुरु-शिष्य परंपरा सदैव अत्यधिक प्रतिष्ठित रही है। शिक्षक, चाहे वह प्राचीनकालीन गुरु की भूमिका में हो या वर्तमानकालीन अध्यापक की भूमिका में, न केवल ज्ञान के वाहक हैं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक नैतिकता, व्यक्तिगत वराष्ट्रीय चरित्र तथा जीवन-मूल्यों के निर्माता भी हैं। हालाँकि आज हम वार्षिक रूप से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, किन्तु यह उत्सव केवल एक तिथि मात्र नहीं, बल्कि शिक्षक के महत्व और उनके योगदान को याद करने का एक अवसर है। प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से वर्तमान विद्यालयी परम्परा तक शिक्षक की भूमिका मेंैक्रमिक परिवर्तनों के बावजूद भी यह एक पवित्र पद माना जाता रहा है।

प्राचीन भारत में प्राथमिक शिक्षण संस्थानों से अधिक केंद्रित रूप था गुरुकुल-जहाँ शिष्य गुरु के आश्रम में निवास करते, न केवल अकादमिक विद्या सीखते, बल्कि जीवनशैली का भी अभ्यास करते थे। इसमें गुरु और शिष्य के बीच गहरा संबंध था, जो केवल पढ़ाई तक सीमित न होकर चरित्र निर्माण,

आत्म नियंत्रण और नैतिक शिक्षा से जुड़ा था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की मूल पद्धतियों में शामिल थे- श्रवण (गुरु की वाणी को सुनना), मनन (उस पर बातचीत और चिंतन करना), निदिध्यासन (गहन ध्यान और आत्मसात करना)। वस्तुतः ज्ञान केवल याद रखने या समझने की क्षमता ही नहीं अपितु आंतरिक अनुभूति और आत्म साक्षात्कार भी था।

भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर तुल्य माना जाता रहा है। गुरु की महत्ता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः॥, श्लोक से स्पष्ट है जहाँ उन्हें दिव्यता, मोक्ष और मार्गदर्शन का स्रोत माना जाता है। भारतीय इतिहास परम्परा में गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र वाल्मीकि, संदीपनी, गुरु धौम्य, वेदव्यास, कश्यप, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान सुधीजन प्रसिद्ध हैं वही भारतीय इतिहास में कौटिल्य जैसे गुरु भी हुए हैं जिन्होंने अखंड भारत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विदित है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, प्रलय व निर्माण उसकी गोद में पलते हैं।

प्राचीन विश्वविद्यालय जैसे तक्षिला, नालंदा व विक्रमशिला में शिक्षक स्वतंत्र रूप से काम करते थे, अपनी पाठशाला चलाते थे और गुरुदक्षिणा की स्वीकारोक्ति पर आधारित व्यवस्था थी, जो अक्सर प्रतीकात्मक होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाण-पत्र नहीं, बल्कि ज्ञान का अंतरण और समाजनिर्माण था।

गुरुकुल और गुरुशिष्य प्रणाली में शिक्षा केवल तकनीकी या अकादमिक नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न आयामों-संस्कार, आत्मअनुशासन,

आध्यात्मिकता, नैतिकता को समाहित करती थी। यह शिक्षा आत्मनियंत्रण और चरित्र निर्माण पर केंद्रित थी।

संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन में गुरु मुख्य भूमिका में रहे हैं। वेद, उपनिषद, दार्शन, धार्मिक कर्मकांड, जीवनशैली का आदान-प्रदान इत्यादि अनेक दृष्टांत हैं जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति और मूल्यों को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने में शिक्षक अग्रणी रहे हैं। इसके साथ ही यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि सनातन व्यवस्था में स्त्री शिक्षा पर भी उतना ही बल दिया गया जितना पुरुष शिक्षा पर। इसके अंतर्गत वैदिक कालीन विदुषीया दृष्टांत रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला जैसी विदुषीया वैदिक ऋचाओं की सुजक व आध्यात्मिक चेतना पर संवाद स्थापित करने वाली रहीं। मध्यकालीन भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के कारण स्त्री शिक्षा में गिरावट अवश्य आयी, किंतु मीराबाई, संत अक्का देवी, सहजोबाई जैसी सांस्कृतिक शिक्षिकाएँ हुईं जिन्होंने समाज को भक्ति व आत्मानुशासन दिया। पुनर्जागरण काल में सावित्री बाईपहले, रमा बाई, जैसी शिक्षिकाओं ने नारी पुनर्चेतना में अभूतपूर्व योगदान दिया।

आधुनिक समय में परंपरागत गुरुकुल मॉडल का पुनरुद्धार हो रहा है- जैसे नागपुर में श्री वेदविद्यावर्षिनी गुरुकुलम्, जहाँ वेद, संस्कृत, धर्मशास्त्र, योगध्यान और आचार संस्कार पढ़ाए जाते हैं, और शिक्षा गैरवाणिज्यिक दृष्टिकोण पर आधारित है। गुरुकुलों का पुनरुत्थान गहन आंतरिक विकास की दिशा में एक सांस्कृतिक पहल है, जो व्यावसायिकता से अलग सांस्कृतिक पुनर्चेतना व गौरवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना का

माध्यम है।

वर्तमान संदर्भ के अंतर्गत भारत में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है-जो डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् की जयंती है। डॉ. राधाकृष्णन् स्वयं एक शिक्षाविद, दार्शनिक और विद्वान थे। वे भारतीय ज्ञान परम्परा व दर्शन के संवाहक थे। जब डॉ. राधाकृष्णन से उनके विद्यार्थियों ने उनके जन्मदिवस की धूमधाम से मनाने का आग्रह किया तो नैतिकता से परिपूर्ण सरल व सहजस्वभाव के धनी डॉ. साहब ने कहा कि यह दिवस पूरे देश के शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाना चाहिए।

गुरुकुलों का पुनरुत्थान, और गुरुशिष्य संबंध का मौलिक स्वरूप आज की शिक्षा को वैल्यू आधारित दृष्टिकोण से समृद्ध बनाता है। शिक्षक केवल ज्ञान का संचरण नहीं करते, बल्कि संस्कृति, संवेदना, और मूल्य उत्थान का सुअवसर प्रदान करते हैं। शिक्षक दिवस हमें याद दिलाता है कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि देश और समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक युगम का आधार है।

यह दिन हमें शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। आज की भौतिकवादी प्रवृत्ति व पाश्चात्य शिक्षा के प्रभुत्व के दौर में एक शिक्षक का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। अब शिक्षक एक विषय विशेषज्ञ ही नहीं अपितु कुशल मार्गदर्शक, नेतृत्वकर्ता और सुसंस्कृत व नैतिक मूल्यों की स्थापना करने वाले की भूमिका हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व निर्माण व मूल्य आधारित दृष्टिकोण विकसित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।

–वासुदेव देवनानी,  
विधानसभा अध्यक्ष,  
राजस्थान

“शिक्षक दिवस” पर एक बेबाक विश्लेषण



राजेन्द्र भागावत

इस आलेख का प्रारंभ मैं उस घटना से करना चाहता हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने साठ के दशक में सुनाई थी जब मैं 15 साल का था। यह बता दूँ कि मेरे पिता उदयपुर के महाराणा भोपाल कॉलेज, जो उसे समय इंटर कॉलेज हुआ करता था, में गणित विषय के विख्यात शिक्षक थे। एक बार उन्हें किसी परिचित के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के उदयपुर स्थित आवास पर जाने का अवसर मिला। जैसे ही पिताजी ने अपना परिचय सुखाड़िया जी को देना प्रारंभ किया तो उन्होंने तत्काल खड़े होकर न केवल उनका अभिवादन किया अपितु यह कहा कि-“मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूँ”। इस प्रकार के सम्मान की कल्पना क्या आज कोई शिक्षक कर सकता है?

मुझे याद है जब पिता जी की आयु लगभग 80 वर्ष की हुई तब उनके शिष्य जो लगभग 70-75 वर्ष के रहे होंगे, वे एक बर उनसे मिलने आते थे, तो उनके चरण स्पर्श कर आदर व्यक्त करते थे। इस प्रकार का रिश्ता शिक्षक और शिक्षार्थी में हुआ करता था, जिसे देखने का सीमांश मुझे मिला। शायद इसी भावना से वे सभी लोग सहमत

होंगे जिन्होंने 1950 से 1970 के बीच विद्यालय में अध्ययन किया था। आज जब हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि शिक्षकों की स्थिति समाज में अब वैसे क्यों नहीं है? क्यों आज समाज में शिक्षकों की वह प्रतिष्ठा नहीं रही एवं क्यों सर्वोच्च प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षक नहीं बनना चाहते? सरकार यह कह सकती है कि वह प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करती है। किंतु यह एक सच्चाई है कि शिक्षकों के ऊपर स्थानांतरण की तलवार सदैव लटककर रखी जाती है। उनके साथ किस प्रकार का अपमानजनक और उपेक्षा पूर्ण व्यवहार शिक्षा प्रशासक और मंत्री गण करते हैं, यह सर्वविदित है। शिक्षकों का अधिकांश समय केवल आँकड़े भरने में और वह सब करने में बीतता है जो शिक्षा से कतई संबंधित नहीं है। शिक्षा विभाग में स्थानांतरण को तो तबादला उद्योग तक कहा जाता है।

सामान्यतः समाज, शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध जीवन पर्यन्त होता है। यह तभी संभव है जब शिक्षक निरंतर एक ही स्थान पर रहे। तब लगातार जुड़ रहे और उसका और विद्यार्थियों का भविष्य भी जुड़ा रहेगा।

शिक्षा समाज की आवश्यकताओं से कितनी दूर हो गई है, यह समझने के लिए मुझे उदयपुर जिला भवन के बुनियादी शिक्षा के प्रसिद्ध शिक्षक दयालचंद जी सोनी का स्मरण हो रहा है। दयाल जी ‘माइसाब’ की शिक्षा की दृष्टि स्वर्णीय विकास की थी और उनकी जीवन दृष्टि गांधी और विष्णु से प्रेरित थी। उनके अनुसार मैकाले की शिक्षा पद्धति का एक ही उद्देश्य था- शोषित, वंचित तथा शासित वर्ग से निकल कर शासक, संपन्न एंड शासक वर्ग में

सम्मिलित होना। इसे उन्होंने ‘वर्गोदय’ शिक्षा का नाम दिया जबकि आवश्यकता सर्वोदयी शिक्षा की थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा कैसी और क्या हो यह समाज के साथ संवाद पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने अपनी बात एक शिक्षार्थी के मुंह से लंबी कविता के रूप में कहलाई थी। यही मेवाड़ी में है जिसका शीर्षक था है “म्हूँ अणभणियो शिक्षित हूँ”, जिसका अर्थ है “मैं बिना पढ़ा-लिखा शिक्षित हूँ”। शिक्षा के मूल मर्म को समझने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह पुस्तिका अवश्य पढ़नी चाहिए। इस कविता के भाव को आज यहां पाठकों के साथ साझा करने का मन कर रहा है। दयाल जी ने यह स्पष्ट किया कि स्कूल जाना और शिक्षा प्राप्त करना एक सम्मान नहीं है। उन्होंने इस कविता में यह चिंता व्यक्त की कि यदि अंग्रेजों के द्वारा दी गई शिक्षा व्यवस्था इसी प्रकार हमने जारी रखी और स्कूलों को ही शिक्षा का पर्याय मान लिया तो देश में देश की प्रगति संभव नहीं है। उनके अनुसार हम बच्चों को केवल ‘स्कूलित’ कर रहे हैं न कि शिक्षिता। जब तक शिक्षा मानव के लिए बहुत आवश्यक गुण जैसे सदाचार, सहकार, संवेदनशीलता, आदि के गुण विद्यार्थियों में विकसित नहीं कर सके तो उसे शिक्षा नहीं कहा जा सकता। दयाल जी उन 18 ग्रामीण शिक्षा विदों में शामिल थे जिन्हें 1954 में डेन्मार्क की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने हेतु भेजा गया था। आज आवश्यकता है उनके विचारों पर संवाद करने की और उन्हें हमारी शिक्षा व्यवस्था में स्थान देने की, ताकि हमारी शिक्षा समाज और देश के लिए अधिक उपयोगी नागरिक तैयार कर सके।

उनका यह भी मानना था कि

राशिफल शुक्रवार 5 सितम्बर, 2025



भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, श्रवण नक्षत्र रात्रि 11:38 तक, शोभन योग दिन 1:53 तक, कौलव करण दिन 3:41 तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेगा।

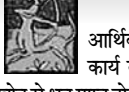
**ग्रह स्थिति:** सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मकर, मंगल-कन्या, बुध-सिंह, गुरु-मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

राजिज सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 11:38 तक है। रवियोग रात्रि 11:38 से आरम्भ होगा। आज प्रदोष व्रत, गोत्रि रात्रि व्रत आरम्भ होगा। आज डा.राधाकृष्ण जयन्ती, शिक्षक दिवस है। आज ईद-ए-मिलाद (बारावफात) है।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** चर सूर्योदय से 7:47 तक, लाभ-अमृत 7:45 से 10:52 तक, शुभ 12:26 तक 1:59 तक, चर 5:06 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 10:30 से 12:00 तक। **सूर्योदय** 6:12, **सूर्यास्त** 6:40

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>मेघ</b> <p>व्यावसायिक कार्यों में ध्यान देना ठीक रहेगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।</p>                       |  <b>सिंह</b> <p>स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दूर होने लगेंगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।</p>                                           |
|  <b>वृष</b> <p>नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। परिवार में शुभ-मंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।</p> |  <b>कन्या</b> <p>व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।</p>           |
|  <b>मिथुन</b> <p>चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।</p>                      |  <b>तुला</b> <p>घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।</p>                    |
|  <b>कर्क</b> <p>परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।</p>                        |  <b>वृश्चिक</b> <p>परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दि.अच्छा रहेगा।</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>धनु</b> <p>आर्थिक कार्यों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। संचालित खोल से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।</p> |  <b>मकर</b> <p>व्यावसायिक कार्यों से संबंधित कार्यों में सफल रहेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक परेशानियां दूर होने लगेंगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।</p> |
|  <b>कुंभ</b> <p>घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। मन में असंतोष बना रहेगा। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।</p>                          |  <b>मीन</b> <p>आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दि.अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।</p>                      |





# जी.एस.टी. दरों के सरलीकरण पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार

गरीब, किसान, व्यापारी और उद्योगपतियों को मिलेगा सीधा लाभ, अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार : भजनलाल शर्मा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वस्तु एवं सेवा कर ( जी.एस.टी. ) की दरों के सरलीकरण को लेकर गुरुवार को विधानसभा परिसर में पत्रकार वार्ता की।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की दरों के सरलीकरण को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी और उद्योगपति सहित समाज के सभी वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को विधानसभा परिसर में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि जीएसटी कार्डसिल द्वारा लिए गए निर्णय के तहत अब चार दरों की जगह केवल दो दरें लागू होंगी। यह निर्णय आमजन की जरूरतों-रोटी, कपड़ा और मकान-को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह कदम आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा और साहसिक निर्णय है, जो न केवल कर प्रणाली को सरल बनाएगा बल्कि पारदर्शिता और व्यापार सुगमता को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से प्रदेश के व्यापारियों को जहां राहत मिलेगी, वहीं आम जनता को भी आवश्यक वस्तुओं पर कम टैक्स का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा

साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार विकास और जनकल्याण की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। शर्मा ने विश्वास जताया कि जीएसटी दरों के इस सरलीकरण से न केवल करदाताओं का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि यह आगामी दीपावली को भी विशेष बना देगा, जब उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत और बाजारों को रफ्तार मिलेगी। यह निर्णय, देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

# राज्य की सभी आंगनबाड़ी बनेंगी “आदर्श” : दिया कुमारी

जर्जर भवन होंगे तत्काल स्थानांतरित, एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट



उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को शासन सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश की आंगनबाड़ियों की दशा सुधारने पर चर्चा की।

जयपुर । राज्य की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को “आदर्श आंगनबाड़ी” के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को लेकर उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फील्ड में जाकर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन सचिवालय में गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्जर और असुरक्षित भवनों को तुरंत ध्वस्त कर आंगनबाड़ी केंद्रों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेन्द्र सोनी, निदेशक वासुदेव मालावत, मुख्य अभियंता ( भवन), समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारी, प्रभारी नंद घर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, सभी जिलों के उपनिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उप मुख्यमंत्री ने जिलेवार प्रगति की समीक्षा करते हुए बजट के समय बड़ और पारदर्शी उपयोग पर बल दिया।

उन्होंने नाराजगी जताई कि कई जिलों में अब तक परम्परागत कार्य शुरू नहीं हुए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सप्ताह में सभी जिलों से कार्यों की अद्यतन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाए और आगामी 15 दिनों में पुनः प्रगति की समीक्षा की जाएगी। दिया कुमारी ने कहा कि आंगनबाड़ी भवनों को सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से युक्त किया जाए। साथ ही, राज्य सरकार के बजट के अतिरिक्त सीएसआर, आपदा सहायता फंड, जिला खनिज फंड और विधायक निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से भी संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए।

## कपड़ों की सिलाई बिगाड़ी, टेलर पर लगाया 10 हजार रुपए का हर्जाना

जयपुर । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने ग्राहक के पेंट-शर्ट के कपड़ों की सिलाई बिगाड़ने को सेवादोष करार देते हुए मैसर्स रॉयल टेलर्स पर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। आयोग ने टेलर को निर्देश दिया है कि वह पेंट-शर्ट के कपड़ों की सिलाई व उनकी कीमत 5,488 रुपए परिवार दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित परिवारी को भुगतान करे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. सुबे सिंह यादव, सदस्य हेमलता अग्रवाल व सदस्य आशुतोष ने यह आदेश विजय कुमार मल्होत्रा के परिवार पर दिए।

परिवार में अधिवक्ता हेमंत कुमार गुप्ता ने बताया कि 11 अगस्त 2021 को परिवारी ने शर्ट व दो पेंट का कपड़ा विपक्षी को सिलाई के लिए दिया था। टेलर ने पन्द्रह सौ रुपए सिलाई देकर की और 22 अगस्त तक डिलीवरी देने को कहा।

परिवारी 14 अगस्त को कपड़ों की ट्रायल के लिए गया तो वह ढीले थे और उनकी फिटिंग सही नहीं थी। विपक्षी ने उसे कहा कि वह इन्हें सही कर देगा, लेकिन परिवारी जब सिले कपड़े लेने गया तो वह खराब ही थे। इसलिए उसे विपक्षी से हर्जा-खर्चा सहित कपड़ों की कीमत दिलवाई जाए। इसके जवाब में विपक्षी टेलर ने कहा कि परिवारी 14 अगस्त को ट्रायल के लिए नहीं आया था। वह अपनी सुविधानुसार 28 अगस्त को ट्रायल के लिए आया और 30 अगस्त को डिलीवरी ले गया। कपड़ों की सिलाई 1560 रुपए थी। इसमें से साठ रुपए छूट देते हुए पन्द्रह सौ रुपए ऑनलाइन भुगतान लिया गया। उसने कोई सेवा दोष नहीं किया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के आयोग ने टेलर पर हर्जाना लगाया है।

## हैरिटेज निगम जयपुर के वार्ड 63 के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत

59 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार भानू सैनी ने जीता पार्षद का चुनाव



हैरिटेज निगम जयपुर के वार्ड 63 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भानू सैनी की जीत के बाद कांग्रेस पार्षदों ने मुख्यालय पर जश्न मनाया।

जयपुर ( कासं )। नगर निगम हैरिटेज के वार्ड 63 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भानू सैनी ने 59 वोट से जीत हासिल की। यहां बागी सीमा मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी रितु नंदवाना को तीसरे नंबर पर धकेला। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हैरिटेज निगम के वार्ड 63 में उपचुनाव की मतगणना पूरी हुई। यहां त्रिकोणीय संघर्ष में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार भानू सैनी ने 59 वोटों से जीत दर्ज करके सबको चौका दिया। इसका कारण यह है कि राज्य में भाजपा की सरकार है और निगम में भी भाजपा की महापौर डॉ. कुसुम यादव हैं। चुनाव जीतने के बाद भानू सैनी ने कहा कि यह वार्ड की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। आने वाले दिनों में वार्ड का विकास कैसे किया जा सके। इसी मुद्दे को लेकर काम करना मेरी प्राथमिकता रहेगी।

दरअसल, हैरिटेज निगम के वार्ड 63 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव की

बागी सीमा मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी रितु नंदवाना को तीसरे नंबर पर धकेला

मतगणना पूरी हुई, जिसके लिए कांग्रेस से भानू सैनी, बीजेपी से रितु नंदवाना और पूर्व पार्षद की पुत्रवधू सीमा मीणा भी चुनावी मैदान में थी। जिसकी वजह से मुकाबला रोचक त्रिकोणीय संघर्ष में बदल गया था। इस मुकाबले में कांग्रेसी प्रत्याशी की जहां जीत हुई है, वहीं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई सुशीला मीणा की पुत्रवधू सीमा मीणा ने बागी चुनाव लड़कर बीजेपी प्रत्याशी रितु नंदवाना को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता परेशान हो चुकी है। निकाय के उपचुनाव में वोट की चोट देकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी

को जानकारी कर तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। जिससे जयपुर में किए गए बीजेपी के विकास के दावों की पोल खुल गई है। आने वाले निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जयपुर में अपना बोंड बनाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी।

बता दें कि नगर निगम हैरिटेज के वार्ड 63 में कुल 8 हजार 132 मतदाता हैं। जिनमें से बुधवार को पार्षद पद के उपचुनाव में सिर्फ 3745 (46.06 प्रतिशत) मतदाताओं ने अपने मतार्थिकार का इस्तेमाल किया। इनमें भानू सैनी को मौजूद पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की बहस सुनने के बाद अदालत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने धरना देकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की और चिकित्सकों को भी रोका। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि 25 जुलाई को झालावाड़ के पिपलौटी गांव में सरकारी स्कूल को छत ढहने से कुछ बच्चों की मौत हो गई थी।

# गौ-माता को अर्थव्यवस्था से जोड़ना सराहनीय कदम : कलराज मिश्र

जयपुर में गौ-महाकुंभ का शुभारंभ हुआ, 7 सितंबर तक जारी रहेगा

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। विद्याधर नगर स्टेडियम में गुरुवार को देवराहा बाबा गौसेवा परिवार की ओर से गौ-महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हुआ। यह महाकुंभ 7 सितंबर तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि को शॉल ओढ़ाकर बुके भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि, गाय को भारतीय संस्कृति में मां का दर्जा प्राप्त है उनको लेकर इस तरह के आयोजन होते हैं ये सराहनीय कदम है। इसी तरह गौ-माता को अर्थव्यवस्था से जोड़ना भी एक तरह से अच्छा कदम है। गौ महाकुंभ 2025 परंपरा और प्रौद्योगिकी का संगम है।

आध्यात्मिक प्रवक्ता सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने कहा कि गाय हमारी सनातन संस्कृति का मुख्य आधार है। गाय का इतना बड़ा आयोजन करने वालों पर गौमाता की कृपा बरस रही है। जहां गौमाता से संबंधित कोई कार्य होता है उसमें किसी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि गौमाता के आशीर्वाद से ही सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों की मदद कर रहे हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने इसके पूर्व में 33 करोड़ आहुतियों के संकल्प के साथ गौ पुष्टि महायज्ञ की शुरुआत की, जिसमें साथ साथ लाख आहुतियों का कार्यक्रम चल रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खरॉं ने कहा कि प्रचीन काल में हमारे पूर्वजों का प्रकृति नदी, पहाड़ और गौमाता से लगाव था। कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत की कृषि में गौमाता का विशेष योगदान है। बैलों से सिंचाई कार्य होता



राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र और आध्यात्मिक प्रवक्ता सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने जयपुर के विद्याधर नगर में गौ-महाकुंभ में शिरकत की।

था। आधुनिकता के इस दौर में कृषि क्षेत्र गौण होता चला गया इसी का परिणाम कि आज प्राकृतिक अस्तंतुलन बढ़ रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य खत्म होता जा रहा है परन्तु अब पुनः इसी कड़ी में पौराणिक संस्कृति की तरफ लौटने के लिए ये गौ महाकुंभ का आयोजन किया गया है। गौमाता के माध्यम से विभिन्न उत्पादों के सृजन का शोध भी किया जा रहा है। भारत सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान सरकार भी इस दिशा में विशेष प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले बजट सत्र में जो किसान भाई बहन के माध्यम से खेती करेंगे उन्हें 25 हजार का अनुदान देने की घोषणा की है। निश्चित रूप से इससे गौ संरक्षण में वृद्धि होगी और भारत देश में खुशहाली का दौर

■ कृषि प्रधान देश भारत में गौमाता का विशेष योगदान, अब पुनः पुरानी संस्कृति की ओर लौटने की जरूरत : मंत्री झाबर सिंह खरॉं

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले बजट सत्र में घोषणा की थी, जो किसान गौवंश से खेती करेंगे उन्हें 25 हजार का अनुदान मिलेगा : यूडीएच मंत्री

से अवगत हैं लेकिन आर्थिक पहलू पर ध्यान दिए बिना गाय का संवर्धन नहीं हो सकता है। गाय के विकास में एसबीआई भी हमारा सहयोगी जिसकी मदद से 2 से 10 करोड़ रुपये तक का लोन आसानी से मिल जाता है। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, पशुपालन किसी भी तरह का कार्य हो उसमें मदद मिल जाती है। कार्यक्रम में महापौर कुसुम यादव, वृंदावन से आए संजीव कृष्ण ठाकुर महाराज, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और गौसेवक शंकर, भाजपा के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज, राजस्थान ग्रामीण बैंक के जनरल मैनेजर श्याम सिंह, एसबीआई के डीजीएम रविशंकर, शिवव्रत जी, गौ महाकुंभ के चेयरमैन डॉ लालसिंह, समन्वयक मुदुल शर्मा, सदस्य डॉ युद्धवीर सिंह बलवदा, डॉ अशोक कुमावत, एस. बी नवगं, सुरेन्द्र अवाना, पूर्ण चौधरी, भरत जयपुरहित , मनीष जैन समेत अन्य गणमान्य मौजूद थे।

# प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही विवाहिता ने की आत्महत्या

जयपुर। कालवाड़ थाना इलाके में कॉम्पिटिशन एजाम की तैयारी कर रही विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फंदे से झूल अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। काफी देर बाद पिता अपने बेटी को बुलाने के लिए कमरे में पहुंचा तो मामले की जानकारी पता चला।

जिसके बाद पीड़ित पिता ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतार अपने कब्जे में लिया और

पोस्टमार्टम के लिए शव को कांक्टिया अस्पताल के मुर्दाघर भिजवाया। पुलिस ने बताया कि मांचवा के नारी का बास निवासी ज्योति यादव (20) ने अज्ञात कारणों के चलते फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले ज्योति की शादी बिंदायका के रहने वाले योगेश यादव से हुई थी। शादी के बाद भी वह अपने पिता बाबुलाल के साथ रहकर कॉम्पिटिशन एजाम की तैयारी कर रही

थी। बुधवार सुबह नाश्ता करने के बाद वह अपने कमरे में वापस चली गईं। कमरे में जाने के बाद उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। करीब 2 घंटे बाद पिता बाबुलाल किसी काम से ज्योति को बुलाने के लिए कमरे में गए तो उन्हें ज्योति फंदे से लटकी मिली। पुलिस को मृतका के पास से किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस अज्ञात कारणों की जांच करने में जुटी है।



राजधानी जयपुर में पिछले चार दिनों से चल रहा बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रहा इस दौरान तेज हवाओं और बारिश से सवाईमानसिंह हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर के बाहर एक विशाल पेड़ धराशायी हो गया जिसे काटकर मौके से हटाया गया।





# मुख्यमंत्री के निर्देश : विधायक अतिवृष्टि क्षेत्र का सघन निरीक्षण करें

## प्रभारी मंत्रियों व सचिवों को भी दो दिन जिलों में राहत व बचाव कार्य की निगरानी के निर्देश दिए

जयपुर, 4 सितंबर राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न हालात को देखते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विधायकों को 5, 6 एवं 7 सितंबर को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि संवेदनशीलता और तत्परता के साथ आमजन की समस्याओं का समाधान करें।

मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों और सचिवों को भी निर्देशित किया है कि वे दो दिन तक जिलों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करें तथा आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण कराएं। भारी बारिश से बनी स्थिति को लेकर विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 1 जून से 1 सितंबर तक प्रदेश में औसत से 56 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। ऐसे में सभी विधायक अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएं और जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर राहत कार्यों को गति दें।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विधायक और प्रभारी मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

करें और राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी लें। साथ ही, प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों का मनोबल बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि निचले इलाकों से समय रहते

लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और भोजन पैकेट, पीने का पानी, दवाइयों व कपड़े जैसी जरूरी सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक नियमित रूप से मीडिया व आम जन को राहत कार्यों की जानकारी दें ताकि किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैले।**

महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित अस्थायी आश्रय की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक नियमित रूप से मीडिया और आमजन को राहत कार्यों की जानकारी दें, ताकि किसी प्रकार की अफवाह न फैले। सोशल मीडिया पर भी हेल्पलाइन नंबर और राहत कार्यों की जानकारी साझा की जाए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा टीमों की तैनाती, पशुओं के टीकाकरण, पेयजल स्रोतों के क्लोरीनेशन, शिविरों में स्वच्छता की निगरानी और लोगों को गंदे पानी से दूर रहने व साफ भोजन-पानी के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए।

## नेता प्रतिपक्ष ...

■ **सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। दूसरी बार की कार्यवाही महज 33 मिनट ही हुई। हंगामे में सरकार ने तीन बिल पास कराये।**

स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। वेल में आकर विधायकों ने मिसबिहेव किया, जो बदरिश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन उसकी भी मर्यादा होती है।

हंगामे और नारेबाजी के बीच विधानसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12:34 बजे स्थगित की गई, और दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू होने पर, फिर से हंगामे के कारण 33 मिनट बाद स्थगित कर दी गई। अब सदन की अगली बैठक 8 सितंबर को होगी।

राजस्थान की राजनीति में यह घटनाक्रम किसानों की समस्याओं और सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर गहराते राजनीतिक संघर्ष का संकेत है। जहां सरकार दावा कर रही है कि हर पीड़ित को सहायता दी जाएगी, वहीं विपक्ष इसे नकारापी बताते हुए, सड़कों से लेकर सदन तक प्रदर्शन कर रहा है।

## जमानती ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय की ओर से अदालती आदेश की पालना में अपना स्पष्टीकरण पेश किया, लेकिन अदालत उससे संतुष्ट नहीं हुई। अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारी अपने स्पष्टीकरण में बता रहे हैं कि प्रकरण में गैर जमानती अपराध के तत्व मौजूद थे, लेकिन जमानत खारिज करने के आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों ने मशीनी अंदाज में जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया। जमानती अपराध में जमानत को अधिकार का विषय माना जाता है, न कि न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहे हैं। कुछ हद तक यह कोर्ट की याचिकाकर्ताओं की हिरासत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि बड़ी संख्या में जमानत याचिकाओं के लंबित होने के कारण वह प्रकरण को प्राथमिकता से नहीं ले सका।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश महर्षि ने बताया कि चित्रकूट थाना पुलिस ने प्रांटीडी डीलर को दुष्कर्म के मामले में फंसाते हैं, न कि न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहे हैं। कुछ हद तक यह कोर्ट की याचिकाकर्ताओं की हिरासत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि बड़ी संख्या में जमानत याचिकाओं के लंबित होने के कारण वह प्रकरण को प्राथमिकता से नहीं ले सका।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश महर्षि ने बताया कि चित्रकूट थाना पुलिस ने प्रांटीडी डीलर को दुष्कर्म के मामले में फंसाते हैं, न कि न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहे हैं। कुछ हद तक यह कोर्ट की याचिकाकर्ताओं की हिरासत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि बड़ी संख्या में जमानत याचिकाओं के लंबित होने के कारण वह प्रकरण को प्राथमिकता से नहीं ले सका।

# सरकार ... सीजन में पहली बार माही बांध के सभी 1 6 गेट खोले

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

तंबाकू, कच्चा तंबाकू और तंबाकू अपशिष्ट, सिगार, चेरुट्स, सिगारिलोस, तंबाकू के विकल्प, वातित पेय (एयरेटेड ड्रिंक्स), कार्बोनेटेड पेय (फल-आधारित भी), कैफीन युक्त पेय, 1,200 सीसी (पेट्रोल) या 1,500 सीसी (डीजल) से बड़ी कार, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, यॉट्स (निजी नौकाएँ), निजी उपयोग के लिए विमान, रेंसिंग कार, ऑनलाइन जुआ और गेमिंग प्लेटफॉर्म। इनमें से अधिकांश वस्तुओं पर पहले ही 28 जीएसटी और क्षतिपूर्क उपकर लग रहा था, जिससे कुल कर भार लगभग 40 तक पहुँच रहा था। जीएसटी परिषद ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को समाप्त कर दिया है और संरचना को केवल दो स्लैब में समेट दिया है: 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। दूधपेस्ट, साबुन, शैम्पू, छोटी कारें, टेलीविजन, और एयर कंडीशनर जैसी रोज़मर्रा की वस्तुएँ अब कम कर – दरों में आएँगी। बहुत सी दवाएँ, दैनिक उपयोग की वस्तुएँ और चिकित्सा-ग्रेड ऑक्सीजन या तो कर-मुक्त कर दी गई हैं या 5 प्रतिशत स्लैब में लाई गई हैं।

■ **उदयपुर की आयड़ नदी से पिछोला में आवक बनी हुई है। दोनों गेट तीन फीट खोलने के बाद भी उदय सागर का जलस्तर बढ़ रहा है।**

आवक और तेज होने पर पानी की निकासी के लिए बांध के सभी 16 गेट खोल दिए गए।

जलसंसाधन विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में 81 मिलीमीटर, ऋषभदेव में 55, नया गांव में 50, वल्लभनगर में 42, सोमकागदर में 40, सलूंबर में

63, दानपुर बांसवाडा में 65, भदेसर चितौड़ में 48, वागान डेम प्रतापगढ़ में 91 और अरनोदे में 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मदार नहर से फतहसागर और सीसारमा नदी से पिछोला में आवक जारी है। आयड़ नदी से उदयसागर में आवक बनी हुई है। दोनों गेट तीन-तीन फीट खोल रखे हैं। उसके बावजूद उदयसागर का जलस्तर बढ़ ही रहा है। पिछले 24 घंटों में उदयसागर के जलस्तर में 2 इंच की बढ़ोतरी हुई है। मादड़ी बांध का गेज 34 फीट के मुकाबले 33 हो गया है। टनल का गेट 6 इंच खोलकर पानी पिछोला में डायवर्ट किया जा रहा है। देवास प्रथम बांध का पानी भी टनल से पिछोला डायवर्ट कर रखा है। देवास प्रथम बांध दो फीट ही खाली है।

# अजमेर : बोराज तालाब की पाल में रिसाव, स्वास्तिक नगर के 8 0 मकान खाली कराये

## जिला प्रशासन को आशंका है कि दरार व रिसाव के कारण तालाब की पाल कभी भी टूट सकती है

■ **तालाब क्षेत्र के बोराज गांव, रावत नगर व स्वास्तिक नगर सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। एन. डी. आर. एफ. और सिविल डिफेंस की टीमों भी तैनात कर दी गई हैं।**

बोराज गांव, रावत नगर व स्वास्तिक नगर सबसे अधिक प्रभावित हैं, कई घरों में पानी भरा हुआ है। जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर तक रिमझिम फुहार के रूप में जारी रहा, जिससे मुख्य सड़कों पर पानी भर गया तथा वाहन डालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला

प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दो-तीन दिन अजमेर संभाग के कई इलाकों में कहीं-कहीं मध्य से तेज बारिश की संभावना है। मानसून के इस सीजन में अब तक एक हजार एमएम बारिश रिकार्ड की जा चुकी है, जिन कॉलोनियों में बरसात का पानी भरा है, वहां, मडपंप लगाकर पानी की निकासी की जा रही है। शहर में लगातार हो रही बारिश से

## कांग्रेस को “ ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

उन्होंने कहा, 2018 से अब तक 7 साल हो गए। वायदे के मुताबिक म्युनिसिपल वेस्ट से या लकड़ी के बुरानि से एक लीटर एथेनॉल भी नहीं बनाया है। और जो 627 करोड़ लीटर एथनॉल बना है, उसमें से 56 प्रतिशत गन्ने से बना है और बाकी अनाज से बना है। कुल 627 करोड़ लीटर एथनॉल में से एक लीटर पानी म्युनिसिपल वेस्ट से नहीं बना। ये शॉकिंग है और बहुत हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। जहां तक पर्यावरण के दावे हैं उनकी चौंकाते वाली सच्चाई कुछ और है। एक लीटर एथनॉल बनाने के लिए तीन हजार लीटर पानी की

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

मिलकर पेपर लीक गैंग के सदस्य विनोद कुमार जाट उर्फ विनोद रेवाड़ से एसआई भर्ती परीक्षा-2021 का लिखित परीक्षा का लीक सॉल्वड पेपर का आट लाख रुपए में सोदा किया था। दोनों परियों का लीक सॉल्वड पेपर विनोद कुमार रेवाड़ के जरिए कार्तिकेय शर्मा के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर लिया था। लीक सॉल्वड पेपर को पढ़ कर रिकू यादव ने एसआई भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा में हिन्दी विषय में 126.01 और सामान्य ज्ञान विषय में 160.65 अंक, इस प्रकार कुल 286.66 अंक प्राप्त किए थे। लेकिन अंतिम रूप से रिकू यादव का चयन नहीं हुआ। एसओजी ने प्रकरण में अब तक 55

प्रशिक्षु उपनिरीक्षक सहित कुल 126 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

### हाई कोर्ट ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

सचिव है। संघ के अध्यक्ष रहे महावीर रांका के खिलाफ सहकारिता विभाग में शिकायत दी गई थी और उन्हें पद से हटाया गया था। वहीं, याचिकाकर्ता ने सहकारिता विभाग में प्रार्थना पत्र पेश कर चुनाव कराने की मांग की थी, जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संघ की जांच विभाग में लंबित चल रही है। याचिका में कहा गया कि इसके बावजूद, बीकानेर में चुनाव कराने के लिए विजित्त का प्रकाशन कराया गया है।



जयपुर में लगातार हो रही बारिश से एम.आई. रोड पर गर्वमेंट हॉस्टल चौराहे के पास गुरुवार सुबह सड़क धंस गई जिससे 10 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया।

सीवरेज लाइन के नजदीक छोटे-छोटे गड्ढों में से बारिश के पानी का रिसाव होने के कारण सड़क धंसी है। नगर निगम हैरिटेज की टीम ने सड़क में बने गड्ढे में से बारिश का पानी निकासकर आसपास खुदाई कार्य शुरू करवाया है, ताकि अगर कहीं और भी मिट्टी का

कटाव हो तो मालूम चल सके।

नगर निगम के चैयटमैन उत्तम शर्मा ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के बाद सीवरेज लाइन डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से सड़क के मामूली गड्ढे ने विशाल रूप ले लिया। नगर निगम की टीम द्वारा पूरी मुसंदैदी के साथ गड्ढे को

भरने की कार्यवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही गड्ढे को भरकर यातायात व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दी जायेगी।

किशनगढ़ जेल के सहायक अभियंता इमरान ने बताया कि पुरानी सीवरेज लाइन लीक होने की वजह से